

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 248) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना 27 जनवरी 2015

सं0 22/नि०सि०(मोति०)—08-08/2007/269—श्री रामानुज सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ढ़ाका नहर नवीकरण अवर प्रमंडल, गोआवरी के विरूद्व वर्ष 2004—05, 2005—06 एवं 2006—07 में ढ़ाका नहर नवीकरण प्रमंडल, ढ़ाका के कराये गये गेटों की मरम्मति कार्य एवं लकड़ी के संधारित लेखा की जॉच उड़नदस्ता अंचल से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं निम्नांकित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गये :—

- 1. नहर के वीयर एवं शीर्ष गेटों की मरम्मित का स्थायी निदान न कर विभागीय शीशम की लकड़ी का प्रावधान प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी सिंचाई के पूर्व गेट मरम्मित के प्राक्कलन में करते हुए लकड़ी की खपत की गयी जो विभागीय नियमों के प्रतिकूल है।
- 2. दिनांक 24.8.06 को हस्त पावती पर लकड़ी का हस्तान्तरण किया गया, जिसे थाना द्वारा जब्त कर लिया गया, परन्तु सिंह द्वारा दिनांक 24.8.06 को जब्त की गई लकड़ी की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को ससमय नहीं दी गयी, साथ ही जांच दल को इससे संबंधित कोई अभिलेख भी नहीं उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक—478 दिनांक 19.4.11 द्वारा श्री रामानुज सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ढ़ाका नहर नवीकरण अवर प्रमंडल, गोआवरी के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह की गेटों की मरम्मित के स्थायी निदान पर नीतिगत निर्णय में इनकी कोई सहभागिता नहीं है तथा पूर्व की प्रक्रिया के तहत गेटों की मरम्मित कार्य में लकड़ी की खपत स्वीकृत कार्यक्रम एवं प्राक्कलन के तहत किया गया है इसके आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध आरोप सं0–1 प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप सं0—2 के संबंध में श्री सिंह के बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से विदित होता है कि दिनांक 24.8.06 को गोआवरी वियर एवं शीर्ष गेटों की मरम्मित हेतु हस्तपावती रसीद पर लकड़ी लेने के क्रम में थाना द्वारा लकड़ी जब्त किया तथा श्री सिंह द्वारा थाना प्रभारी से सम्पर्क स्थापित कर लकड़ी छुड़ाने का प्रयास किया गया तथा उसकी सूचना मौखिक रूप से कार्यपालक अभियंता को दी गई। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 58 शि0 (मोति0) दिनांक 06.09.14 में भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भी थाना प्रभारी, ढाका से सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थित की पूर्ण जानकारी दी गई। फिर भी श्री सिंह को लिखित रूप से मामले की जानकारी

उच्च पदाधिकारी को देनी चाहिए थी। आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा बचाव बयान के साथ ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे प्रमाणित हो सके कि थाना में जब्त लकड़ी की सूचना लिखित रूप से उच्चाधिकारियों को दी गई, जिसके लिए वे दोषी हैं।

उड़नदस्ता जॉच दल के मंतव्य कंडिका 4.00 में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है। अतएव अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रामानुज, तत्कालीन सहायक अभियंता, ढाका नहर नवीकरण अवर प्रमंडल, गोआवरी के विरूद्ध थाना द्वारा जब्त लकड़ी की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को ससमय नहीं देने के प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या—583 दिनांक 19.05.14 द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित किया गया —

(1) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

उक्त दंड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक— शून्य दिनांक 22.06.2014 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वस्तुतः केवल यही आरोप प्रमाणित हुआ कि इनके द्वारा लकड़ी जब्ती की लिखित सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय नहीं दी गई थी, किन्तु इनके द्वारा मौखिक सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय प्राप्त हो गई थी तथा उच्चाधिकारियों द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई थी।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि केवल आंशिक रूप से लिखित सूचना नहीं देने के लिए दोषी है। अतएव पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0—583 दिनांक 19.05.14 द्वारा दिये गये दण्ड में आंशिक संशोधन करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक की जगह पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिंह को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:--

(1) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्ड श्री सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ढ़ाका नहर नवीकरण प्रमण्डल, ढ़ाका सम्प्रति सहायक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–2, दानापुर को संसूचित किया जाता है।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 248-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in